GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 65
TO BE ANSWERED ON 22/07/2022

COLD STORAGE FACILITIES IN TAMIL NADU

*65. SHRI TIRUCHI SIVA:

Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government has analyzed the problems of farmers related to the lack of cold storage in the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether government proposes to increase the number of cold storages in the State of Tamil Nadu;

(d) if so, the details thereof; and

(e) whether districts in Tamil Nadu have been identified and funds allocated for the said purpose and if so, the details thereof?

ANSWER

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(SHRI NARENDRA SINGH TOMAR)

(a) to (e): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARA (a) TO (e) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 65 BY SHRI TIRUCHI SIVA TO BE ANSWERED ON 22.07.2022.

(a) & (b): A study "All India Cold-chain Infrastructure Capacity (AICIC-2015)" was conducted by NABARD Consultancy Services (NABCONS) in 2015 and it assessed the required capacity of cold storages at that time as 351.00 lakh MT against the existing capacity of 318.23 lakh MT in 2014.

As per available information, there are 8361 cold storages in the country with the capacity of 381.10 lakh MT as on date. The State-wise details are at **Annexure**-I.

(c) to (d): Government of India is implementing various schemes to increase the number of cold storage facility throughout the country including Tamil Nadu under which financial assistance is provided for setting up of cold storages.

Department of Agriculture & Farmers Welfare is implementing Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) under which financial assistance is provided for various horticulture activities including setting up of cold storages. The component is demand/entrepreneur driven for which Government assistance in the form of credit linked back ended subsidy is available at the rate of 35% of the project cost in general areas and 50% of the project cost in hilly and scheduled areas.

Besides, National Horticulture Board (NHB) is implementing a scheme namely "Capital Investment Subsidy for Construction/Expansion /Modernization of Cold Storages and Storages for Horticulture Products". Under the scheme, credit linked back-ended subsidy at the rate of 35% of the capital cost of the project in general areas and 50% in case of North East, hilly & scheduled areas for construction/expansion/modernization of cold storage and Controlled Atmosphere (CA) storage of capacity above 5000 MT and up to 10000 MT is available. In case of North East region, the units with capacity above 1000 MT are also eligible for assistance.

Ministry of Food Processing Industries (MOFPI) is implementing a Scheme for Integrated Cold Chain, Value Addition and Preservation Infrastructure as one of the component of Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana with the objective of reducing post-harvest losses of horticulture and non-horticulture produce and providing remunerative price to farmers for their produce. Under the scheme, Ministry provides financial assistance in the form of grant-in-aid at the rate of 35%

for general areas and 50% for North East and Himalayan States, ITDP areas and Islands for storage and transport infrastructure and at the rate of 50% and 75% respectively for value addition and processing infrastructure subject to a maximum grant-in-aid of Rs. 10 crore per project for setting up integrated cold chain projects including irradiation facility. Standalone cold storages are not covered under the Scheme.

Further, to strengthen agriculture infrastructure in the country, Government has launched Agriculture Infrastructure Funds (AIF) of Rs. 1.00 lakh crore. Under AIF, there is provision for collateral free term loan upto Rs. 2.00 crore and interest subvention of 3% on the term loan availed for creation of post harvest infrastructure including establishment of cold storages.

(e): Under MIDH scheme, the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare allocates funds to State Horticulture Mission (SHM). The SHM in turn allocate funds to the Districts based upon the approved Annual Action Plan. District level details of the funds allocated, released and utilized are maintained at State level.

As per available information, there are 187 cold storages with capacity of 3.95 lakh MT established under various schemes of Government of India in the State of Tamil Nadu.

Annexure-I

State wise distribution of Cold Storages as on 18.07.2022 in the Country

S. No.	Name of the State	Total	
		No.	Capacity (MT)
1	Andaman & Nicobar Islands (UT)	4	2210
2	Andhra Pradesh &Telangana	442	1703321
3	Arunachal Pradesh	2	6000
4	Assam	41	197096
5	Bihar	312	1475667
6	Chandigarh (UT)	7	12462
7	Chhattisgarh	99	487263
8	Delhi	97	129857
9	Goa	29	7705
10	Gujarat	985	3869543
11	Haryana	370	846588
12	Himachal Pradesh	81	167312
13	Jammu & Kashmir	72	263853
14	Jharkhand	58	236680
15	Karnataka	229	694991
16	Kerala	201	96405
17	Lakshadweep (UT)	1	15
18	Madhya Pradesh	309	1331532
19	Maharashtra	627	1043182
20	Manipur	2	4500
21	Meghalaya	4	8200
22	Mizoram	3	4071
23	Nagaland	5	8150
24	Orissa	181	576688
25	Pondicherry (UT)	3	85
26	Punjab	726	2451501
27	Rajasthan	187	631569
28	Sikkim	2	2100
29	Tamil Nadu	187	395940
30	Telangana	74	411518
31	Tripura	17	51140
32	Uttar Pradesh	2429	14836735
33	Uttrakhand	60	206621
34	West Bengal	515	5948316
	Total	**8361**	**38108816**

(Source: Directorate of Marketing and Inspection (DMI) upto 2009, National Horticulture Board (NHB), National Horticulture Mission (NHM), Horticulture Mission for North East & Himalayan States (HMNEH)) and MoFPI

*****

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 65
22 जुलाई, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: तमिलनाडु में शीतगृह की सुविधाएं:

***65. श्री तिरुची शिवा:**

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में शीतगृह की कमी से संबंधित किसानों की समस्याओं का विश्लेषण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार तमिलनाडु राज्य में शीतग्रहों की संख्या में वृद्धि करने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या उक्त प्रयोजनार्थ तमिलनाडु में जिलों की पहचान कर ली गई है और निधि आवंटित कर दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"तमिलनाडु में शीतगृह की सुविधाएं" के संबंध में दिनांक 22 जुलाई, 2022 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 65 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) एवं (ख): नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (NABCONS) द्वारा 2015 में "ऑल इंडिया कोल्ड-चेन इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी (AICIC-2015)" एक अध्ययन किया गया था और इसने 2014 में 318.23 लाख एमटी की मौजूदा क्षमता की तुलना में उस समय शीत भंडारण की आवश्यक क्षमता 351.00 लाख एमटी का आकलन किया था।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देश में अब तक 381. 10 लाख एमटी क्षमता वाले 8361 शीत भंडारण हैं। राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

(ग) एवं (घ): भारत सरकार तमिलनाडु सहित पूरे देश में शीत भंडारण सुविधाओं की संख्या बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है जिसके तहत शीत भंडारण की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) को कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत शीत भंडारण की स्थापना सहित विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह घटक मांग/उद्यमी प्रेरित है जिसके लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 35% और पहाड़ी तथा अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना लागत के 50% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता उपलब्ध है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) "बागवानी उत्पादों के लिए शीत भंडारण और भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी" नामक एक योजना लागू कर रहा है। इस योजना के तहत, सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत के 35 प्रतिशत और शीत भंडारण के निर्माण/विस्तार/ आधुनिकीकरण के लिए पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% पर तथा 5000 एमटी से अधिक और 10000 एमटी तक की क्षमता के नियंत्रित वातावरण (सीए) भंडारण के लिए क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी उपलब्ध है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में, 1000 एमटी से अधिक क्षमता वाली यूनिट भी सहायता के लिए पात्र हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के एक घटक के रूप में एकीकृत शीत श्रृंखला, मूल्य संवर्धन और संरक्षण अवसंरचना के लिए एक योजना लागू कर रहा है जिसका उद्देश्य बागवानी और गैर-बागवानी उत्पादों के फसलोपरांत नुकसान को कम करना है और किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान कर रहा है। इस योजना के तहत, मंत्रालय भंडारण और परिवहन अवसंरचना के लिए सामान्य क्षेत्रों के लिए

35 प्रतिशत और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों, आईटीडीपी क्षेत्रों और द्वीपों के लिए 50 प्रतिशत की दर पर और विकिरण सुविधा सहित एकीकृत शीत श्रृंखला परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रति परियोजना 10 करोड़ रु. की अधिकतम अनुदान सहायता के अध्यधीन मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण अवसंरचना के लिए क्रमशः 50% और 75%, रुपये की दर पर अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत स्टैंडअलोन शीत भंडारण को कवर नहीं किया गया है।

इसके अलावा, देश में कृषि अवसंरचना को मजबूत करने के लिए, सरकार ने 1.00 लाख करोड़ रुपये का कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) शुरू किया है। एआईएफ के 2.00 करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त सावधि ऋण और शीत भंडारण की स्थापना सहित फसलोपरांत अवसंरचना के निर्माण के लिए लिए गए सावधि ऋण पर 3 प्रतिशत की ब्याज छूट का प्रावधान है।

(ङ.): एमआईडीएच योजना के तहत, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय राज्य बागवानी मिशन (एसएचएम) को निधियां आवंटित करता है। फिर एसएचएम अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के आधार पर जिलों को निधियां आवंटित करता है। आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का जिला स्तर का विवरण का रख-रखाव राज्य स्तर पर किया जाता है ।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत 3.95 लाख एमटी की क्षमता वाले 187 शीत भंडारण स्थापित हैं।

अनुबंध -I

दिनांक 18.07.2022 की स्थिति के अनुसार देश में सृजित शीत भंडारण के वितरण का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल	
		संख्या	क्षमता(एमटी)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी)	4	2210
2	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	442	1703321
3	अरुणाचल प्रदेश	2	6000
4	असम	41	197096
5	बिहार	312	1475667
6	चंडीगढ़ (यूटी)	7	12462
7	छत्तीसगढ़	99	487263
8	दिल्ली	97	129857
9	गोवा	29	7705
10	गुजरात	985	3869543
11	हरियाणा	370	846588
12	हिमाचल प्रदेश	81	167312
13	जम्मू और कश्मीर	72	263853
14	झारखंड	58	236680
15	कर्नाटक	229	694991
16	केरल	201	96405
17	लक्षद्वीप (यूटी)	1	15
18	मध्य प्रदेश	309	1331532
19	महाराष्ट्र	627	1043182
20	मणिपुर	2	4500
21	मेघालय	4	8200
22	मिजोरम	3	4071
23	नागालैंड	5	8150
24	ओडिशा	181	576688
25	पुडुचेरी (यूटी)	3	85
26	पंजाब	726	2451501
27	राजस्थान	187	631569
28	सिक्किम	2	2100
29	तमिलनाडु	187	395940
30	तेलंगाना	74	411518
31	त्रिपुरा	17	51140
32	उत्तर प्रदेश	2429	14836735
33	उत्तराखंड	60	206621
34	पश्चिम बंगाल	515	5948316
	कुल	**8361**	**38108816**

(स्रोत: 2009 तक विपणन और निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई), राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच)) और एमओएफपीआई)

*****

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Any supplementaries?

SHRI G.K. VASAN: Sir, in this House, I am talking as a proud farmer. The farmer community is the backbone of India. In Tamil, we say, only if the farmers keep their leg in the clay soil, can we keep our hand in the food. *...(Interruptions)...* That is a saying in Tamil, Sir. I would like to say to the hon. Minister that there are lakhs and lakhs of farmers in Tamil Nadu cultivating various types of crops. *...(Interruptions)...* The need of the hour for the State, for their better livelihood, is definitely cold storages. Today, there are 187 cold storages with a capacity of only 3.95 lakh metric tons. In the 2015 survey of NABARD, *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, be brief. *...(Interruptions)...*

SHRI G.K. VASAN: I would like to request the hon. Minister...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have to put the question, Vasan ji. *...(Interruptions)...*

SHRI G.K. VASAN: A new survey has to be done in the interest of the State of Tamil Nadu. *...(Interruptions)...*

श्री उपसभापतिः आप किसी माननीय सदस्य को बोलने से रोक नहीं सकते। ...**(व्यवधान)**...

SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE: In 2015, there was a survey conducted by NABCONS to assess the required capacity of cold storages in the country. As per the survey, there was a demand for the cold storages. *...(Interruptions)...* The Government of India, in the last five years, has encouraged setting up of cold storages in the country. *...(Interruptions)...* That is why the capacity has been increased *...(Interruptions)...* In 2014, the capacity was 318 lakh metric tonnes only. It has now been increased to 381 lakh metric tonnes in 2022. *...(Interruptions)...* 8,361 cold storages have been set up around the country. The Government of India, under the leadership of Modi ji, has set up Agriculture Infrastructure Fund. Also, under the MIDH scheme and Rashtriya Krishi Vikas Yojana, any State can plan for their development in the State. डिस्ट्रिक्ट को क्या चाहिए, डिस्ट्रिक्ट की आवश्यकता के आधार पर ... **(व्यवधान)** ...Any district can plan for cold storage, warehouses, etc. *...(Interruptions)...* They can plan for their district. *...(Interruptions)...* There is a provision in the Agriculture Infrastructure Fund. *...(Interruptions)...* There is the

MIDH scheme. ...*(Interruptions)*... That is why, States should make use of this fund and plan for the districts. ...*(Interruptions)*... हम स्वतंत्रता दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... We are giving independence to the States. ...*(Interruptions)*... They can plan for their districts. ...*(Interruptions)*... डिस्ट्रिक्ट की,...**(व्यवधान)**...जिले की आवश्यकता क्या है? ...**(व्यवधान)**...जिले की आवश्यकता के आधार पर वे प्लान कर सकते हैं।...**(व्यवधान)**...सर, यह इंडिपेंडेंस राज्यों को है। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Kanakamedala Ravindra Kumar. ...*(Interruptions)*... This question relates to Tamil Nadu. ...*(Interruptions)*... जो माननीय सदस्य दूसरे माननीय सदस्यों को बोलने नहीं देना चाहते हैं...**(व्यवधान)**...या पीछे जा कर प्लैकार्ड्स दिखा रहे हैं,...**(व्यवधान)**...यह गलत है। ...**(व्यवधान)**...कृपया अपनी सीट पर जाएं। ...**(व्यवधान)**... Shri Kanakamedala Ravindra Kumar. ...*(Interruptions)*...

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, to strengthen the agriculture infrastructure in the country, the Government has launched the Agriculture Infrastructure Fund. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This question relates to Tamil Nadu. ...*(Interruptions)*...

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Yes, Sir. ...*(Interruptions)*... Sir, the first part of the question relates to the country. ...*(Interruptions)*... I am asking about the country. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is about Tamil Nadu. ...*(Interruptions)*...

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Sir, Question No.65 relates to the country. ...*(Interruptions)*... I am asking about the country. ...*(Interruptions)*... I would like to know whether the Central Government has allotted any funds to the State Governments with regard to cold storage. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This question relates to cold storage facilities in Tamil Nadu. ...*(Interruptions)*... If the Minister wants to reply, she can. ...*(Interruptions)*...

SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE: Sir, Agriculture Infrastructure Fund is allocated to each and every State. ...*(Interruptions)*... They can make use of the Agriculture Infrastructure Fund in every State. ...*(Interruptions)*... Also, RKVY scheme and

MIDH scheme are there. ...*(Interruptions)*... Even Tamil Nadu can make use of this and other States can also make use of this. ...*(Interruptions)*... 13 हज़ार करोड़ रुपये का ...**(व्यवधान)**...प्रोजेक्ट है।...**(व्यवधान)**... यह आया है, लेकिन सर, ...**(व्यवधान)**...अभी बाकी फंड्स बाकी हैं।...**(व्यवधान)**...बाकी जिलों में भी,...**(व्यवधान)**...राज्यों में भी इस फंड का यूज़ करने के लिए ...**(व्यवधान)**... आप प्रोजेक्ट भेज सकते हैं। ...**(व्यवधान)**...सर, बहुत सारी स्टेट्स ने डिस्ट्रिक्ट एग्रिकल्चरल प्लान नहीं बनाया है।...**(व्यवधान)**... डिस्ट्रिक्ट एग्रिकल्चरल प्लान बनाना, ...**(व्यवधान)**... उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजना है।...**(व्यवधान)**...सर, हम इसको यहाँ से सैंक्शन करने के लिए तैयार हैं। ...**(व्यवधान)**...उपसभापति जी, मैं सभी स्टेट्स से, ...**(व्यवधान)**...मैं सभी राज्यों से विनती करती हूं कि आपकी स्टेट में, जिले में क्या चाहिए...**(व्यवधान)**...आपको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, ...**(व्यवधान)**...वेयरहाउस चाहिए, ...**(व्यवधान)**... पैकेजिंग हाउस चाहिए...**(व्यवधान)**...ब्रैंडिंग चाहिए...**(व्यवधान)**...आपको जो चाहिए, उसके आधार पर प्लान बनाइए, ...**(व्यवधान)**...उसको भेजिए। ...**(व्यवधान)**...हम उसको यहाँ से ..**(व्यवधान)**...सैंक्शन करने के लिए तैयार हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : प्रश्न संख्या 66, माननीय राम नाथ ठाकुर जी, आप अपना पहला सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछिए।